



451 :2

ਪੇਜ : 2

सबसे बड़ी खबरें

# अत्यरीकरण

RNI No.- DELHIN/2016/68043

नई दिल्ली संस्करण, नई दिल्ली, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025, वर्ष : 9, अंक : 15 पृष्ठ : 08, मूल्य : 02 रुपया

नई दिल्ली से प्रकाशित व दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसारित

## सांक्षेप समाचार

आज उपेक्षित रही परंपराएं  
और विरासत पुनर्जीवित हो  
गई : जयशंकर

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लंबे समय से उपेक्षित रही गईं और विरासत अब पुनर्जीवित हो गई हैं। ज्यादा भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है और भारतीय प्रथाओं को नया प्रोत्साहन और गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसका सार यह है कि इंडिया आज भारत बन चुका है। यह बात बुधवार को जयशंकर एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) परिवर्तन को मान्यता देता है और मुझे यकीन है कि यह इसे अपने भविष्य के कार्यों में शामिल करेगा। आईसीसीआर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जयशंकर ने कहा कि किसी भी संस्था के लिए 75 साल विकास और विस्तार का अहम समय होता है...। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय और भी अहम हो जाता है। खासकर उस परिवेश को देखते हुए जिसमें ये संस्थाएं काम करती हैं। जयशंकर ने कहा कि हमारा राष्ट्र और हमारा समाज काफी बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज देश में हमारी संस्कृति, विरासत और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वास्तव में हम अपनी परंपराओं के कई पहलूओं पर गर्व महसूस करते हैं, जो अब कई पहल और योजनाओं में दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे पर्यटन को बढ़ावा देना और विश्व धरोहर स्थलों की सं या में वृद्धि इनमें शामिल है।

नई दिल्ली / भव्य खबर/ श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगल को दिए गए ऐतिहासिक फैसले वे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या राज अब विधानसभा में पारित विधेयक अनिश्चितकाल के लिए रोक नहीं सकता वैसे कोर्ट ने आपने आदेश में स्पष्ट है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक सकते। कोर्ट का यह निर्णय तमिलनाडु रकार बनाम राज्यपाल मामले में अंजिससे न केवल तमिलनाडु, बल्कि के अन्य राज्यों की चुनी हुई सरकार बड़ी राहत मिलती दिख रही है।

विमान लैंड करते ही आया पायलट  
को अटैक और हो गई मौत

नई दिल्ली। श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान पूरी करने के बाद एयर इंडिया ए स्प्रेस के एक पायलट की नई दिल्ली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। पायलट की हाल ही में शादी हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना विमान के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तरने के कुछ ही समय बाद हुई। एयरलाइन के मुताबिक दिल्ली में विमान के उत्तरने के बाद पायलट की अपनामश पदस्थान हवाई अड्डे रखे गए के एक जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बज्जपात से 23 लोगों की मौत हो गई। इसमें सीवान में 4, जमुई में 3, सहरसा, अररिया और सारण में दो-दो, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, दरभंगा, अरबल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुग्र, कटिहार और भागलपुर में 1-1 लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में धरों में रहें और सुरक्षित रहें। बिहार में बज्जपात से ज्यादा मौतों के कई कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, मानसून के दौरान नमी और बारिश के पैटन में बदलाव और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के दौरान लोगों का लिये कुछ सारांश तरल पदार्थों के सपक में आन से फलता है, आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध या इंजेक्शन द्वारा उपकरण साझा करने के माध्यम से। एडस का अर्थ है एकवायर्ड इम्युनो डेफिसियेंसी सिन्ड्रोम। एडस, एचआईवी संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। जैसे कि एचआईवी इफेक्शन लगभग 10 वर्षों में एडस में बदल जाता है। एडस से पोडित लोगों में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत कम होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उन्हें अतिरिक्त बीमारियां हो सकती हैं जो सकेत करती हैं कि वे एडस में बदल गए हैं।

का अस्पताल नहीं हूजा जार उस पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉ टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब पायलट ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए एयर इंडिया ए सप्रेस उड़ान का संचालन कर रहा था। एयरलाइन के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में उत्तरने के बाद कैप्टन अरमान ने विमान के अंदर उल्टी की, डिस्पैच ऑफिस जाने से पहले उनमें परेशानी के शुरूआती लक्षण दिखे, जहां बाद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आईजीआई हवाई अड्डे के एयर इंडिया ए सप्रेस सुविधाओं में चिकित्सा कर्मियों को तुरंत घटनास्थल पर बुलाया गया, लेकिन उनकी त्वारित प्रतिक्रिया और अस्पताल ले जाने के बावजूद, पायलट अरमान को बचाया नहीं जा सका। उसे हवाई अड्डे

# पर एयरलाइन के डिस्पैच कार्यालय में अटैक आया

## शिवराज सिंह घौहान ने सपरिवार पथुपति नाथ सिंह में साझा केता

शिवाराज सिंह चौहान बिस्टेक देशों के कृषि मर्त्रियों की बैठक के लिए काठमांडू (नेपाल) में हैं। उन्होंने वहां बैठक के बाद गुरुवार को परिवार के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किये और मंदिर प्रांगण में रुद्राक्ष और हरसिंगार के पौधे रोपे। शिवाराज सिंह ने इस बारे में सोशल मीडिया ए स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि बिस्टेक देशों के कृषि मर्त्रियों की बैठक के लिए काठमांडू में हूं। बैठक के बाद आज परिवार के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किये। यहां मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ आमीय भेंट हुई। भगवान पशुपतिनाथ के पावन प्रांगण में रुद्राक्ष और हरसिंगार के पौधे रोपने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा, चार वर्ष पूर्व नर्मदा मैया की गोद में रोपे संकल्प का बीज पशुपति महादेव के आंगन तक पहुंच गया है। मैं तो बस एक निमि हूं, कर्म का यह मार्ग, शिव की प्रेरणा है। महादेव की कृपा बनी रहे और प्रकृति की सेवा का यह संकल्प इसी प्रकार पल्लवित, पुष्पित हो गया।

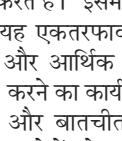
- ट्रूप ने ज्यादातर ढेशों पर लगाए गए शुल्क को अचानक 22 दिनों के लिए राशीकरण करने का ऐसा काम किया।

अमेरिकी टैटियार के खिलाफ चीन का नया लाज ! टेट गॉर में यारों को बना रहा हशिरार तैरिक बाजार पर मुंदराया संकल

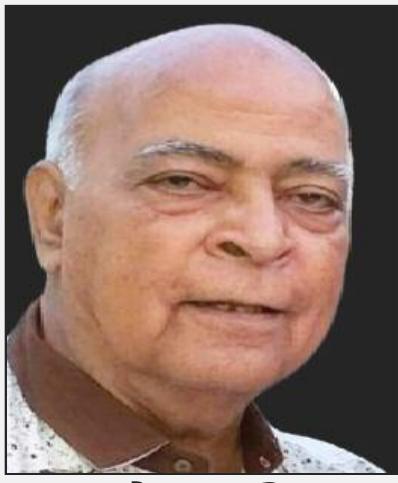
बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 84 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, जो बहुस्पतिवार से प्रभावी हो गया है। इन घटनाक्रम के बीच चीन ने अब यूरोप पर ध्यान केंद्रित किया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन के बीच फोन पर बातचीत हुई जिसके जरिए ह्यायिनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है।<sup>11</sup> दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ह्याशिन्हुआ<sup>12</sup> ने अपनी एक खबर में कहा, ह्यायि चीन यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि चीन और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच जो समझ बनी है उस पर मिल कर अमल किया जा सके। चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ और यूरोपीय संघ के

व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त सेफकोविक के बीच अमेरिकी शुल्क के मुद्रे पर मंगलवार को बीडियो कॉफ़ियन्स के माध्यम से चर्चा हुई। शिन्हुआ ने अपनी खबर में वांग के हवाले से कहा कि शुल्क "सभी देशों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन करते हैं, डब्ल्यूटीओ के नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हैं, नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और वैश्वक आर्थिक व्यवस्था की

100



स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।" इसमें कहा गया, ह्याँ यह एकत्रफावाद, संरक्षणवाद और आर्थिक तौर पर परेशान करने का कार्य है। चीन परामर्श और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को हल करने के लिए तैयार है लेकिन अगर अमेरिका अपने रुख पर अड़ता है तो चीन अंत तक लड़ेगा।" वांग ने आसियान देशों से भी बात की है जबकि प्रधानमंत्री ली ने व्यापारिक दिग्जिटों से मुलाकात की है। शिन्हआ ने ली के हवाले से कहा कि चीन ने हायू पूरा मूल्यांकन कर लिया है और सभी तरह की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार है और वह स्थिति के हिसाब से नीतियां पेश करेगा।" देशों को लाम्बांद करने की चीन की कोशिशों के बीच ऐसा नहीं है सभी देश चीन के साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। बहुत से ऐसे देश जिनका चीन के साथ विवाद रहा है वे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ॲस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एथनी अल्बनी ने संवाददाताओं से कहा, ह्याँहम अपनी बात करते हैं और ॲस्ट्रेलिया का रुख यह है कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार ही अच्छा है। हम सभी देशों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन हम ॲस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित के लिए खड़े हैं।" माना जा रहा है कि भारत ने सहयोग संबंधी चीन के आह्वान को तबज्जो नहीं दी है। वहीं चीन का करीबी देश रूस पर परिवृश्य में कहीं नहीं है।



# अशोक भाटिया

देशभर में वक्फ कानून को  
लेकर राजनीतिक और  
सामाजिक माहौल लगातार  
ग्रमाता जा रहा है। कहीं इस  
कानून के समर्थन में बोलने  
पर लोगों को पीटा जा रहा है।  
तो कहीं विरोध के नाम पर  
हिंसा और आगजनी हो रही  
है। सड़क से सदन तक, वक्फ  
कानून को लेकर डराने वाली  
तस्वीरें सामने आ रही हैं।

संपादकीय

# राज्यपाल पर लगाम



अमृता आर. पंडित

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु, सरकार बनाम राज्यपाल के मामले में जो फैसला दिया है, वह कई अर्थों में एक निर्णयक फैसला है जिसने तमिलनाडु, के वर्तमान राज्यपाल आर. एन. रवि की भूमिका को न केवल कड़ी आलोचना के घेरे में खड़ा किया, बल्कि उसे सीमित भी कर दिया। इस फैसले ने राज्यपालों द्वारा विशेषकर उन राज्यों में जहां केंद्र सरकार के विरोधी दलों की सरकारें हैं, सरकारों पर मनमानी तरीके से अपने अधिकारों द्वारा अंकुश लगाने के प्रयासों को लगभग समाप्त कर दिया है। राज्यपाल की भूमिका को सीमित तो कर दिया है, साथ ही उसे नियमबद्ध भी कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार के विधिवत पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के मामले में अनिश्चित अवधि तक लंबित नहीं रख सकते। अब आगे से कोई राज्यपाल किसी भी पारित विधेयक को एक महीने से अधिक अपने पास लंबित नहीं रख सकता। अगर यह विधेयक राज्यपाल के द्वारा वापस कर दिया जाता है, और पुनर्विचार के लिए पुनः उसके पास आता है तो वह उसे राष्ट्रपति को भी की ओर अग्रसर हैं तो उनके समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। गिराता स्वास्थ्य, परिवारिक जिमेदारियां और तकनीकी पिछड़ापन उन्हें परेशान कर रही हैं। उनके समक्ष आर्थिक अस्थिरता सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ती उम्र के कारण उनके पास काम-धंधे का भी अभाव है। पत्रकारीय कार्य के अलावा उन्हें कोई दूसरा काम भी नहीं आता, और ना ही कभी कुछ दूसरा करने की सोची। संघर्षील पत्रकारों को यह अच्छी तरह पता है कि पत्रकारिता एक ऐसा पेश है जिसमें ना तो कोई निश्चित वेतनमान होता है और ना ही कोई सुनिश्चित भविष्य निधि। ज्यादातर मीडिया हाउस में कार्यरत पत्रकारों को कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रीलांस पत्रकारों की स्थिति तो और भी बदतर है। नई तकनीकी की वजह से अब उनसे कोई कंटेंट भी लिखवाना नहीं चाहता। ऐसे में अपने बच्चों के लिए वह रोटी का जुगाड़ कहां से कर पाएंगे? वह एक बड़ी समस्या है। ऐसे कई पत्रकार हैं जो आज अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें कोई आर्थिक सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को ऐसे पत्रकारों के कल्याण के लिए पेंशन योजना जरूर लाग



१५ सीमा लेख

पिंतन-मनन

**सर्वत्यापी है आत्मा**

केवल वह जो क्षणिक है, छोटा या नर है, उसे ही सुरक्षा की आवश्यकता है; जो स्थायी है, बड़ा या विशाल है, उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं। सुरक्षा का अर्थ है समय विशेष को लंबा कर देना; इसीलिए सुरक्षा परिवर्तन में बाधक भी होती है। पूर्ण सुरक्षा की स्थिति में रूपांतरण नहीं हो सकता। सुरक्षा के बिना इच्छित रूपांतरण नहीं हो सकता। एक बीज को पौधे में परिवर्तित होने के लिए सुरक्षा चाहिए; एक पौधे के वृक्ष बनने के लिए सुरक्षा चाहिए। अत्यधिक सुरक्षा रूपांतरण में या तो सहायक हो सकती है या बाधक, इसीलिए रक्षक को यह समझ होनी चाहिए कि किस मात्रा तक उसे रक्षा करनी है। सुरक्षा और रूपांतरण- दोनों काल और समय के अनुसार होते हैं और समय से परे होने के लिए इन नियमों का सम्मान आवश्यक है। सुरक्षा एक विशेष समय और नर चीजों तक ही संमित है। चिकित्सक कब तक किसी को स्वस्थ रख सकता है या बचा सकता है? सदा के लिए? नहीं। सत्य को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। शांति और खुशी को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे क्षणिक नहीं। तुम्हारे शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं; तुम्हारे मन को सुरक्षा की जरूरत है, स्वरूप को नहीं। आत्मा केवल मन और शरीर का समिक्षण नहीं है। आत्मा न मन है, न शरीर। शरीर के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है तुम्हें सचेत करना कि तुम कितने सुंदर हो; और तुमको जागरूक करना कि तुम जिन आदर्शों का सम्मान करते हो, उन सभी को तुम अपने जीवन में ढालकर, अपने चारों ओर एक दिव्य-जगत की सृष्टि करो। जो योगासन तुम करते हो, वह शरीर के लिए और जो ध्यान करते हो, वह मन के लिए है। शांत हो या विचलित; मन, मन ही रहता है। रोगी हो या निरोगी; शरीर, शरीर ही रहता है। आत्मा सर्वव्यापी है। शरीर के किसी अंग को उत्तेजित करने से मजा आता है सब का आभास होता है।

## **वक्फ कानून के विरोध में क्यों हो रही है हिंसा ?**

**द**ृश्य में नया वक्फ कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि आठ अप्रैल से पूरे देश में वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। बता दें, बीते सप्ताह हस्सद में लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मजरी दी थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि नया वक्फ कानून देश में कब से लागू होगा। नए वक्फ अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे विवादित संशोधन वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिमों को शामिल करना है। इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं डाली गई हैं। देशभर में वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहात्मा लगातार गरमता जा रहा है। कहीं इस कानून के समर्थन में बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है, तो कहीं विरोध के नाम पर हिंसा और आगजनी हो रही है। सड़क से सदन तक, वक्फ कानून को लेकर डरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तब हैं जब वक्फ कानून का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। बड़ी बात ये है कि 15 या 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ डाली गई अर्जी पर सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश के संभल में जाहिद सैफी को इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था। कानपुर में ओला टैक्सी ड्राइवर ने एक वरिष्ठ अधिकारी की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह फोन पर वक्फ कानून की चर्चा कर रहे थे। मणिपुर में बीजेपी नेता अली असगर का घर जला दिया गया क्योंकि उन्होंने इस कानून का समर्थन किया था। वर्हां, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, मंगलवार को बंगल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग लगा दी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में इंठर की धारा 163 लागू करनी पड़ी है। इन इलाकों में अगले 48 घंटों तक निषेधाज्ञा लागू रही और किसी भी प्रकार के सामूहिक जमावड़े पर रोक होगी। एक वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और इसके बाद मची अफरातफरी में कुछ पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी गई। दरअसल वक्फ बोर्ड अधिनियम के पारित होने



अल्पसंख्यक इस नए कानून से प्रसन्न हैं क्योंकि अधिकांश लोग वक्फ बोर्ड व उसके अवैध कब्जाधारिये के आतंक से ब्रह्म हैं स्मरण रहे कि भारत एक संप्रभु पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी मूल आत्मा सर्विधान है। किसी भी संगठन द्वारा यह कहन या संकेत देना कि उनके लिए मजहबी कानून सर्विधान से ऊपर है, न केवल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी अपमान है हम केंद्र सरकार और न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि इस पत्र प्रकरण के गंभीरता से लिया जाए क्योंकि इसी मानसिकता ने पहले ही भारत का विभाजन कराया था। सर्विधान से ऊपर मजहब को रखने वाली सोच देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए भी घातक हो सकती है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इन मतभेदों के बीच वाद और संवाद की जगह हिंसक सोच क्यों? क्या समाज में सहनशीलता घट रही है और साम्प्रदायिकता बढ़ रही है? क्या किसी मुद्दे पर वैचारिक मतभेद समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है? क्या भारत जैसे देश में हिंसा वाली सोच अब सबसे बड़ा खतरा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन तीन कृपित कानून का विरोध हुआ तो हिंसा की जगह सत्याग्रह की राह आंदोलनकारियों ने चुनी। सीएए का विरोध हुआ तो आंदोलनकारियों ने हिंसा की बजाय अहिंसात्मक प्रदर्शन की राह अपनाई। लेकिन वक्फ कानून के विरोध-प्रदर्शन के बीच कुछ जगह हिंसा की घटनाएं सामने आईं। क्या हिंसक सोच, वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों के आंदोलन को कमज़ोर कर सकता है? इन किसी मुद्दे पर

## वरिष्ठ पत्रकारों के हित में थोस कदम जरूरी !

करनी चाहिए ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। बढ़ती उम्र के साथ उनके स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है। कई बीमारियाँ घेर रही हैं। पैसे के अभाव में वह महगे इलाज नहीं करा पाते। महगे हेल्थ इंश्योरेंस उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि समय रहते उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। हालांकि केंद्र सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत सुविधाएं प्रदान की हैं, जो नाकामी है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा भी कई पत्रकार हैं जो इन सुविधाओं से वचित हैं। पत्रकार कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार प्रदत्त सुविधाओं को भी और बढ़ाया जाना चाहिए। पहले प्रतिष्ठित पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत मिलती थी परंतु कोविड महामारी के बाद यह सुविधा बंद कर दी गई है। भारत के कई राज्य सरकारों ने पत्रकारों के तहत में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग आदि शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोपनीयता, बिहार, केरल, हरियाणा, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन, देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की कोई ठोस योजना अभी तब नहीं बनाई गई है। दिल्ली जो विरास्ती-अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता का केंद्र है। वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सरकार को विशेष लागू करनी चाहिए। पत्रकारों वे लिए पेंशन योजना स्वास्थ्य बीमा योजना तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन एवं रियायत, आवासीय सुविधा एवं आपातकालीन सहायता कोष आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी सरकार को पत्रकारों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पत्रकार अपनी लेखनी और विचारों से न केवल हांसा आईना दिखाते हैं बल्कि किसी कार्य की आलोचना करते हैं। वे हमें सही मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। इनमें कोई दो राय नहीं है कि समय-समय पर पत्रकारों ने सभी रकार की उपलब्धियों को भी हमेशा जन-जन तब पहुंचाने का काम किया है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने देश की पत्रकारिता को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब वे अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं तो उनके लिए आर्थिक और



सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार को पत्रकारों की इन आवश्यकताओं के मद्देनजर ठोस नीतियां बनानी चाहिए ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारीय कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पत्रकारों को अपनी समस्याओं से बारम्बार सरकार और देश के नीति-नियंत्रणों से अपने हक में अपनी आवश्यकताओं के मद्देनजर अपनी आवाज बुलंट करनी चाहिए। प्रतिदिन आप दूसरों के लिए लिखते-पढ़ते रहे। जीवन भर देश और समाजहित में अपनी रचनाओं को आकार दिया। आज जब आपके हालात अच्छे नहीं तो आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आपमें जो लिखते-पढ़ते का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर शिश्चारपूर्वक अपनी बात को स-रकार तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? लोकतंत्र में जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आप करते रहे, आज समय आ गया है कि उसे अपने हक के लिए इस्तेमाल करें। हम कलम के सिपाही हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता। मगर जरूरत पड़ी तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें सड़कों पर भी उतरना चाहिए। मेरी राय में सरकार को सड़क पर उतरने के लिए हमें मजबूर नहीं करना चाहिए। पत्रकारों निवेदन पर गैर करना चाहिए।

## बाजार में छिपे अवसर: भारतीय निवेशकों के लिए एक विवेकपूर्ण मार्गदर्शन"



अब लोगों को जोखिम भरी लगने लगी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे मंचों पर मौजूद निवेश सलाहकारों की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके सुझाव लगातार असफल साबित हो रहे हैं। हालांकि यह मंदी पहली बार नहीं आई है। 2008 की वैश्विक मंदी और 2020 की कोविड-19 गिरावं जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जब बाजार ने समय साथ फिर से मजबूती पाई। बाजार में गिरावट एक सामान्य चक्र का हिस्सा है, जो समय-समय पर वैश्विक और घरेलू परिस्थितियों से प्रभावित होता है भारत की आर्थिक बुनियाद अभी भी मजबूत मानी जाती है। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों का मानना है कि भारत 2025 तक 7% के अप्पापां ज

डी.पी वृद्धि दर बनाए रख सकता है। देश की युवा जनसंख्या, डिजिटलीकरण की गति और पोएलआई स्कीम जैसे सरकारी प्रयास भारत को दीर्घकालिक रूप से निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं। ऐसे में निवेश-टक्कों के लिए जरूरी है कि वे घबराने की बजाय धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ें। अगर निवेश एसआईपी के जरिए हो रहा है तो उसे जारी रखना ही समझदारी है, क्योंकि गिरते बाजार में नियमित निवेश लंबे समय में औसत लागत को कम करता है। साथ ही, यह समय पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करने का है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आंशिक रूप से लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स की ओर झुकना चाहिए। संगठित निवेश जैसे गोल्ड ईंटीएफ या स्पष्टपारी लॉन्ट-मॉ











